रही है और क्या उनकी बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं ;

(ख) जिन राज्यों में इन परिषदों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं उनमें इस दिशा में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों में ये बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुमति ओरांव) : (क) और (ग) राज्यों के नाम तथा आदिवासी सलाहकार परिषदें हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार आयोजित की गई बैठकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) राज्यों का आदिवासी विकास से संबंधित इस मंच के महत्व के बारे में बताया गया है और उन्हें कम से कम वर्ष में दो बार नियमित रूप से आदिवासी सलाहकार परिषद् की बैठकें आयोजित करने के लिए बार-बार स्मरण कराया जाता है। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस मामले में लिखा गया है।

विवरण

राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों का कार्यकरण

आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठकें

राज्य	1986–87	1987–88	1988–89
1. आन्ध्र प्रदेश	1	2	सूचित नहीं किया गया —
2. बिहार	शून्य	1	1
3. गुजरात	शून्य	1	1
4. मध्य प्रदेश	2	1	1
5. महाराष्ट्र	1	1	1
6. हिमाचल प्रदेश	2	2	2
7. राजस्थान	शून्य	1	1
8. पश्चिमी बंगाल	2	सूचित नहीं किया गया	1
9. उड़ीसा	1	1	2
10. तमिलनाडु	गठित नहीं की गई		